दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, बुधवार 04 दिसम्बर 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 66

महत्वपूर्ण एवं खास

सरकार की रेलवे के भी निजीकरण की तैयारीः प्रियंका

नईदिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने रेलवे को बहुत खराब स्थिति में पहुंचा दिया है और अब उसकी देश की इस 'जीवन रेखा' को भी बेचने की तैयारी है। वाड्रा ने ट्वीट किया, भारतीय रेल देश की लाइफलाइन है। अब भाजपा सरकार ने भारतीय रेल को भी सबसे बुरी हालत में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार में सार्वजानिक उपक्रमों के निजीकरण का कौशल है और इस स्किल के तहत अब उसकी रेलवे को भी बेचने की योजना है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार का स्किल बनाना नहीं बेचना है। अब कुछ दिनों बाद बाकी सरकारी उपक्रमों की तरह भाजपा सरकार रेलवे को भी बेचना शुरू कर देगी। इसके साथ ही उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संसद के पटल पर सोमवार को पेश उस रिपोर्ट से संबंधी खबर भी पोस्ट की है जिसमे कहा गया है कि पिछले एक दशक में रेलवे का संचालन सबसे खराब हालात में पहुंच गया है।

कोविन्द ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने आज राष्ट्रपति भवन में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति के साथ-साथ राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जन्म तीन दिसंबर 1884 को जीरादेई (बिहार) में हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था।

सभी सुविधाओं के लिए एक ही कार्ड लाने की कोई योजना नहीं: सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश के सभी नागरिकों को समस्त सुविधाओं के लिए एक ही कार्ड जारी करने की कोई योजना को लेकर सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार क पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने इस संबंध में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि फिलहाल सभी सुविधाओं के लिए एक ही कार्ड का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि उन्होंने बताया कि सरकार ने एक अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने तथा उसमें ताजा जानकारी शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित एक मंत्रिसमूह की सिफारिश पर भारत के प्रत्येक नागरिक के अनिवार्य पंजीकरण को निर्दिष्ट करने वाली धारा 14ए को तीन दिसंबर 2004 से नागरिकता अधिनियम, 1955 में शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि नागिरकता कानून 1955 के तहत बनाये गये नागरिकता (नागरिक पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम-2003 के नियम 3 के उप नियम (4) के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 2010 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया और 2015 में इसे नवीनीकृत किया।

संसद ने दी एसपीजी बिल में संशोधनों पर मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मंगलवार को एसपीजी संशोधन बिल 2019 पारित हो गया। हालांकि इस दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने वॉकआउट किया। राज्यसभा में बिल पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बिल का गांधी परिवार से कोई लेना देना नहीं है। न ही इसे राजनीतिक रंजिश की मंशा के साथ लाया गया है।

अमित शाह ने कहा कि यह सच नहीं है कि गांधी परिवार को ध्यान में रखते हुए हम एसपीजी बिल लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि बिल लाने से पहले ही खतरे की समीक्षा करने के बाद गांधी परिवार की सुरक्षा हटाई गई थी। उन्होंने कहा कि कोई राजनीति हित नहीं और न ही किसी सुरक्षा में चूक होने देंगे। गांधी परिवार के साथ

» राज्यसभा में शाह ने गिन-गिनकर विपक्ष को दिया करारा जवाब

130 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा का जिम्मा भाजपा के पास है।

एसपीजी एक्ट में पांचवां संशोधन

गृह मंत्री ने कहा कि एसपीजी एक्ट में यह पांचवां संशोधन है। यह संशोधन गांधी परिवार को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि पिछले चार संशोधनों को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है न कि किसी एक परिवार को ध्यान में रखकर।

हम परिवार के नहीं परिवारवाद के खिलाफ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा को प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। आखिर सिर्फ एसपीजी की मांग ही क्यों? एसपीजी कवर सिर्फ देश के मुखिया के लिए है, हम हर किसी को यह सुरक्षा नहीं दे सकते। हम किसी एक परिवार के खिलाफ नहीं बल्कि परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ हैं।

वाम दल को राजनीतिक द्वेष पर बोलने का हक नहीं

अमित शाह ने बिल पर बहस के दौरान वाम दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीपीआई (एम) को तो हक ही नहीं है ये कहने का कि राजनीतिक द्वेष से सरकार चल रही है। आपने इसी द्वेष से केरल में भाजपा के 120 कार्यकर्ता मार दिए। अमित शाह के बयान पर वाम दल के सदस्यों ने विरोध जताया।

गांधी परिवार की सुरक्षा में एसपीजी के ही पूर्व जवान

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि गांधी परिवार की सुरक्षा में वही जवान तैनात हैं, जो कभी एसपीजी में रह चुके हैं। उन्होंने कहा, श्एसपीजी में बीएसएफ के 33 प्रतिशत, सीआरपीएफ से 33 से 34 प्रतिशत, सीआईएसएफ से 17 प्रतिशत, आईटीबीपी से 9 प्रतिशत और अन्य राज्यों की पुलिस से 1 प्रतिशत जवान हैं। पांच साल बाद इन्हें इनके संगठन में वापस भेज दिया जाता है।श् उन्होंने बताया कि गांधी परिवार के तीनों सदस्यों की सुरक्षा में वहीं लोग लगाए गए हैं जो कभी एसपीजी में रह चुके हैं। अमित शाह ने कहा कि गांधी परिवार को वही सुरक्षा मिली हुई है, जो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति के पास है।

प्याज की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आप सांसदों का संसद में प्रदर्शन

नईदिल्ली (आरएनएस)। देशभर में खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में प्याज की बढ़ती कीमतों के विरोध में आम आदमी पार्टी (आप) के सांसदों ने मंगलवार को प्याज की माला पहनकर प्रदर्शन किया। आप के दो राज्यसभा सदस्यों- संजय सिंह और सुशील कुमार ने बढ़ती कीमतों के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन आपूर्ति मंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की।

संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते हुए आप नेताओं ने केंद्र से सवाल किया कि प्याज आखिर क्यों इतनी डरावनी होती जा रही है, और उपभोक्ताओं को इसके लिए ऊंची कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। सिंह ने कहा, इसमें कोई घोटाला प्रतीत होता है। हम यह मुद्दा संसद के अंदर भी उठाएंगे।

भारत निर्वाचन आयोग पीपीआरटीएमएस लागू करेगा

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण की प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा की है। इसके बारे में नये दिशा-निर्देश 1 जनवरी, 2020 लागू किये जाएंगे। आवेदकों के आवेदनों की स्थिति का पता लगाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 'राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली' (पीपीआरटीएमएस) लागू की जाएगी। पीपीआरटीएमएस की मुख्य विशेषता है कि आवेदक (1 जनवरी, 2020 से राजनीतिक दल के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाला) अपने आवेदन की प्रगति का पता लगा सकेगा तथा एसएमएस एवं ई-मेल के द्वारा अद्यतन स्थिति से अवगत हो सकेगा। इसके लिए आवेदक को अपने आवेदन में दल/आवेदक का मोबाइल नम्बर और ई-मेल पता दर्ज करना होगा।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण नियंत्रित होता है। उपर्युक्त धारा के तहत निर्वाचन आयोग में पंजीकरण के लिए इच्छुक दल को अपने गठन की तिथि के बाद 30 दिनों की अवधि में, नाम, पता, विभिन्न इकाइयों की सदस्यता का विवरण, पदाधिकारियों के नाम, आदि मूलभूत विवरण सहित निर्धारित प्रारूप में आयोग के पास एक आवेदन दाखिल करना होता है, जैसा कि उपर्युक्त धारा की उपधारा (4) के तहत आवश्यक है और पंजीकरण हेतु दिशा-निर्देशों में किये गये उल्लेख के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए की उपधारा (6) के तहत निर्दिष्ट किया गया है।

आतंकवादी घटनाओं में आई कमी, घुसपैठ की कोशिशें बढ़ीं

नई दिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई मामलों पर जवाब दिया। जिसमें नाबालिग लड़कियों और महिलाओं को मानव तस्करों द्वारा खाड़ी देश भेजने, कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद हुए घुसपैठ और हमले के मामले और जम्मू-कश्मीर में हुई गैर-कश्मीरी नागरिकों की हत्या शामिल है।

सबसे पहले गृह मंत्रालय ने लोकसभा में खाड़ी देशों में महिलाओं और किशोरियों के अपहरण और तस्करी की रिपोर्ट पर कहा, श्बड़े पैमाने पर महिलाओं और किशोरियों के अपहरण और खाड़ी देशों में उनकी

तस्करी की घटनाएं भारत सरकार के ध्यान में नहीं आई हैं। हालांकि कभी-कभी विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ भारतीय महिलाएं प्रवास की अनुमति के बगैर (इमिग्रेशन क्लीयकेंस) विदेशों में रोजगार चाहती हैं, विशेषकर खाड़ी देशों में। ऐसी महिलाएं रोजगार से जुड़ी विभिन्न समस्याओं की चपेट में आ जाती हैं। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में हुए हमले और घुसपैठ के मामलों पर मंत्रालय ने कहा, श्पांच अगस्त के बाद आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में कमी आई है। पांच अगस्त 2019 से 27 नवंबर 2019 के बीच 88 ऐसी घटनाएं हुई हैं। वहीं 12 अप्रैल 2019 से 4 अगस्त 2019 में इन घटनाओं की संख्या 106 थी। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों की संख्या में वृद्धि हुई है। पांच अगस्त 2019 से 31 अक्तूबर 2019 के बीच 84 बार इस तरह की कोशिश की गई है। वहीं यह संख्या नौ मई 2019 से चार अगस्त 2019 के बीच 53 थी। गृह मंत्रालय ने बताया कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कितने नागरिकों की हत्या की गई जिसमें गैर-कश्मीरी मजदूर भी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा, श्जम्मू-कश्मीर सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 19 नागरिकों जिसमें गैर-कश्मीरी मजदूर भी शामिल हैं, उनकी आतंकलाद से संबंधित घटनाओं में हत्या की गई है। जम्मू-कश्मीर सरकार की मौजूदा योजना के तहत आतंकवाद से संबंधित हिंसा में मारे गए नागरिकों के परिजनों को एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है।

भारतीय जल क्षेत्र में जासूसी कर रहा था चीनी पोत को नौसेना ने खदेड़ा

नईदिल्ली (आरएनएस)। नौसेना ने हाल ही में पोर्ट ब्लेयर के पास भारतीय जल क्षेत्र में घुसे चीनी पोत को खदेड़ दिया। शक है कि चीन का ये जहाज अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पोर्ट ब्लेयर के पास भारतीय हितों के खिलाफ जासूसी गतिविधियों में संलिप्त थी। चीनी जहाज 'शी यान 1' को पोर्ट ब्लेयर के पास संदिग्ध गतिविधियां करते नोटिस किया गया था।

यह जलपोत पोर्ट ब्लेयर के पास भारतीय जल क्षेत्र में कथित रूप से अनुसंधान गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने इसका पता लगाया वैसे ही

भारतीय नौसेना सक्रिय हो गई। नौसेना ने अपने एक युद्धपोत को इसकी निगरानी के लिए भेजा। भारतीय कानून के अनुसार कोई भी विदेशी जहाज भारतीय जल क्षेत्र में किसी भी प्रकार का शोध या अन्वेषण गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता। इसके बाद भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने पूरा संयम बरतते हुए चीनी अनुसंधान पोत को भारतीय जल क्षेत्र से बाहर जाने के लिए कहा। भारतीय नौसेना का आदेश पाते ही चीनी जलपोत भारत के जलक्षेत्र से बाहर भाग गया।

बता दें, चीनी नौसेना अक्सर एंटी-पायरेसी गश्त के उद्देश्य के साथ भारतीय जल में प्रवेश करती है लेकिन भारत इसे पूरी तरह से नहीं खरीदता क्योंकि चीनी युद्धपोत परमाणु और पारंपरिक पनडुब्बियों के साथ होते हैं जो एंटी-पाइरेसी ऑपरेशन में कोई मतलब नहीं रखते हैं।

देश के सामने जल्द आएगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः निशंक

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नयी शिक्षा नीति से विश्व में भारत का गौरव स्थापित होगा और कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जल्दी ही जनता के सामने होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में आयोजित कार्यक्रम स्वच्छ कैंपस रैंकिंग 2019 को संबोधित करते हुए निशंक ने छात्रों से प्रतिदिन एक लीटर पानी बचाने की शपथ लेने और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करने का आग्रह किया।

भारत-नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण-14 शुरु

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच 14वां द्विपक्षीय वार्षिक सैन्य अभ्यास सूर्य किरण-14 मंगलवार से नेपाल के रुपन्देही जिले के सलिझंडी में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल (एनएबीएस) में शुरू हुआ। दोनों देशों के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पिछले साल जून में आयोजित किया गया था।

इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और नेपाल की सेना के बीच बटालियन स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन करना है, जिसमें विमानन के पहलुओं सहित जंगल में युद्ध, पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों, मानवीय सहायता, आपदा राहत अभियानों, चिकित्सा और पर्यावरण संरक्षण के लिए सैन्य स्तर पर पारस्परिकता बढ़ाना शामिल

रहेगा।

अभ्यास के तहत, जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में विद्रोही गतिविधियों से निपटने तथा आतंकवादी विरोधी कार्रवाइयों से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्यान, प्रदर्शन और अभ्यास आयोजित किए जाएंगे। दोनों सेनाएं ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करने से संबंधित अपने बहुमूल्य अनुभवों को भी साझा करेंगी और जरूरत के अनुसार संयुक्त अभियानों के लिए अभ्यासों और प्रक्रियाओं में सुधार भी करेंगी।

विश्व निशक्त दिवस का नाम बदलने की जरूरतः नायडू

» दिव्यांगजन पुनर्वास में यूपी को सर्वोत्तम राष्ट्रीय पुरस्कार

नई दिल्ली (आरएनएस)। उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने विश्व निशक्त दिवस पर पुरस्कार वितरित करते हुए विश्व के सभी देशों से अपील की है कि इस दिवस के नाम को बदलकर विश्व दिव्यांगजन दिवस कर देना चाहिए। वहीं इस मौके पर दिव्यांगजन पुनर्वास के क्षेत्र के बेहतर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है।

विश्व निशक्त दिवस पर यहां नई दिल्ली के विज्ञान भवन में में मंगलवार को अपने संबोधन में उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि विश्व निशक्त दिवस का नाम बदलकर 'दिव्यांग जन दिवस' कर देना चाहिए। समारोह में नायडू ने दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में हासिल उपलब्धियों और किए कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी बांटेते हुए भारत और विश्वभर के लोगों से अपील की है कि उनके सुझाव पर विचार करें क्योंकि दिव्यांग लोगों ने साबित किया है कि वे दूसरों के लिए एक मिसाल हैं। उन्होंने यह इच्छा जाहिर की कि विशेष रूप से सक्षम लोगों को सिनेमा हॉल, सभागारों, सार्वजनिक स्थानों और

अन्य स्थानों पर जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कॉर्पोरेट तथा निजी क्षेत्रों से इस संबंध में एक भूमिका निभाने का आग्रह किया।

केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यहां विज्ञान भवन में विश्व निशक्त दिवस को मनाने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में दिव्यांगजन पुनर्वास के क्षेत्र में सर्वोत्तम राज्य के रूप में चुने गये उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

तीन सुरक्षा कर्मी निलंबित, उच्च स्तरीय जांच जारीः शाह

» प्रियंका गांधी की सुरक्षा सेंध मामला

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सुरक्षा घेरे में सेंध के मामले में तीन सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और घटना की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है।

गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी।शाह ने उच्च सदन में विशेष सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि 25 नवंबर को प्रियंका गांधी की सुरक्षा कर रहे सुरक्षा अधिकारियों को यह जानकारी मिली थी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी काली सफारी में उनसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि एसपीजी सुरक्षा प्राप्त राहुल गांधी और प्रियंका के पति राबर्ट वाड्रा के वाहनों की आवश्यक जांच आम तौर पर नहीं होती। उन्होंने कहा कि यह एक संयोग ही था कि उसी वक्त मेरठ की कांग्रेस की एक महिला नेता चार अन्य कार्यकर्ताओं के साथ काली सफारी में प्रियंका के आवास पर पहुंच गयीं और सुरक्षा कर्मियों ने राहुल गांधी का वाहन समझकर उनके वाहन की जांच नहीं की। उन्होंने कहा कि इन लोगों का काले रंग के सफारी वाहन में वहां पहुंचना महज एक संयोग था। गृह मंत्री ने कहा कि इस संयोग के बावजूद प्रियंका गांधी की सुरक्षा में लगे तीन कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और इस मामले में उच्च स्तरीय जांच चल रही है। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के बी के हरिप्रसाद सहित कुछ सदस्यों ने प्रियंका की सुरक्षा घेरे में सेंध लगाये जाने पर गहरी चिंता जताते हुए इस बारे में सरकार से कई सवाल पूछे थे। इन सवालों की ओर इशारा करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की सुरक्षा का मामला काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की सुरक्षा से जुड़े इस अति महत्वपूर्ण मामले को संसद में उठाने या मीडिया में जाने के बजाय उन्हें, सीआरपीएफ या कांग्रेस नेता की सुरक्षा पर निगरानी रख रहे आईजी स्तर के अधिकारी को पत्र लिखकर उन्हें इस बात की सूचना देते।

बौखलाए वाड्रा ने साधा मोदी सरकार पर निशाना

एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के बाद पहली बार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आवास पर सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। इसे लेकर उनके पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि पूरे देश में सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा है। उन्होंने लिखा कि यह प्रियंका, मेरी बेटी या बेटे, मेरे या गांधी परिवार की सुरक्षा के बारे में नहीं है। यह हमारे नागरिकों, विशेष रूप से हमारे देश की महिलाओं को सुरक्षित रखने और सुरक्षित महसूस कराने को लेकर है। पूरे देश में सुरक्षा से समझौता किया जाता है।